

नदीजोड़ परियोजनाओं की मुश्किलें

पहली चिंता खर्च की है। इस मद में 5.60 लाख करोड़ रुपए खर्च का अनुमान लगाया गया था। यह खर्च और ज्यादा हो सकता है क्योंकि इसी तरह की एक योजना चार साल पहले चीन में शुरू की गई है, जहाँ सिर्फ दो नदियों को जोड़ने पर करीब चार हजार अरब रुपए का खर्च आया है। चीन ने अपनी सबसे बड़ी नदी यांगत्जे और देश की नंबर दो पीली नदी की जलधारा को जोड़ने की पांच दशक पुरानी परियोजना के जरिए तकरीबन डेढ़ अरब घनमीटर पानी हर साल सूखाग्रस्त शांदोंग प्रांत में भेजने का लक्ष्य रखा है, ताकि इस प्रांत में पानी की कमी के अंभीर संकट से निपटा जा सके। करीब आधी सदी तक चली बहस के बाद चीनी मंत्रिमंडल ने इस महत्वाकांक्षी परियोजना को दिसंबर, 2002 में मंजूरी दी थी, जिसके बाद लाखों लोगों को विस्थापित किया गया। चीन के उदाहरण को सामने रख कर देखें तो कहा जा सकता है कि हमारे देश में नदियों को परस्पर जोड़ना कितना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।



ब रसों से देश में जिस नदीज़ोड़ परियोजना को लेकर बहसों और ऊहापेह का दैर चलता रहा है, लगता है कि अब उस पर छाया कुहासा कुछ कम हो सकेगा। हाल में केंद्रीय जल संसाधन मंत्री उमा भारती ने एलान किया कि इस साल की पहली तिमाही में ही केन-बेतवा को जोड़ने का काम शुरू हो जाएगा। बुदेलखण्ड में पानी की दिवकर दूर करने वाली इस परियोजना को अब सिर्फ पर्यावरण मंत्रालय की आखिरी मंजूरी की दरकार है, उसके बाद इससे 6.35 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई और 78 मेगावॉट बिजली परियोजना को पानी मिल सकेगा। इससे पहले देश में आधि प्रदेश की दो प्रमुख नदियों-गोदावरी और कृष्णा को औपचारिक रूप से जोड़ा जा चुका है।

नदाजाड़ पारखयाजना का वकालत मरुच्यत दा आधारा पर की जाती रही है। एक तो सूखे और पानी की कमी से जूझने वाले इलाकों को सतत पानी देने के उद्देश्य से और दूसरे, मानसून या अधिक वर्षा की स्थिति में नदियों में आने वाले अतिरिक्त पानी के कारण पैदा

होने वाली बाढ़ की समस्या से निपटने के संदर्भ में। हिमालयी हिस्से की चौदह नदियाँ सदानीरा हैं। मानसून के दौरान उनमें अत्यधिक पानी आ जाता है, जो देश के रुम्म और मध्य के हवालांकरण में बाढ़ के नियंत्रण के

पर उत्तर जार नव्वा पकड़ इलायगा भन बाढ़ पर पिंगारक
दृश्य उपस्थित करता है। ऐसे में अगर इन नदियों को
गरमी और सर्दी के मौसम में सूखे जाने वाली मध्य
और दक्षिण भारत की नदियों से जोड़ दिया जाए, तो
सूखे और बाढ़ की समस्याओं का एक झटके में
समाधान हो सकता है।

यही नहीं, दिल्ली-मुंबई जैसे महानगर पेयजल के लिए
पड़ोसी गाजों और बांधों से मिलने वाले पानी पर
आधिक हैं। ऐसे कई इलाके हैं, जो सिंचाई और पेयजल
के दिल्ली पानी के अभाव से जड़ा होता है। ये विशेष इलाके

के लिए पाना की जमाप से ऊँझा रह है, पर्याप्त उनके आसपास की नदियां या तो भयानक रूप से प्रदूषित हैं या बरसात के बाद प्राय सूखा जाती हैं। सबसे अहम यह होगा कि सिंचाई के लिए मानसुन पर हमारी निर्भरता का नदीजोड़ परियोजना से स्थायी समाधान

निकल सकता है। अगर यह याजना कारबर रहता है, तो न सिर्फ कुछ असिचित क्षेत्रों के लिए सिंचाई और बिजली उत्पादन के लिए पानी का बंदोवस्त हो जाएगा, बल्कि कई जगहों पर बाढ़ का संकट भी नहीं रहेगा। पर नदियों को जोड़ने का सपना जितना बड़ा है,

उसके तामोर हाने की राह में मुश्किले भी उतनी ही ज्यादा हैं। पहली चिंता खर्च की है। इस मद में 5.60 लाख करोड़ रुपए खर्च का अनुमान लगाया गया था। यह खर्च और ज्यादा हो सकता है क्योंकि इसी तरह की एक योजना चार साल पहले चीन में शुरू की गई है, जहाँ

सप्त दा नादया का जाड़न पर कराव चार हजार अरब
रुपए का खर्च आया है। चीन ने अपनी सबसे बड़ी नदी
यांगतंजे और देश की नंबर दो पीली नदी की जलधारा
को जोड़ने की पाच दशक पुरानी परियोजना के जरिए
तकरीबन डेढ़ अरब घनमीटर पानी हर साल
सुखाग्रस्त शांदोंग प्रांत में भेजने का लक्ष्य रखा है,
ताकि इस प्रांत में पानी की कमी के गंभीर संकट से
निपटा जा सके।

साइबर जोखिम



स रकारी आंकड़ों के अनुसार 2019 में भारतीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम द्वारा चिह्नित किए गए साइबर हमलों की संख्या चार लाख से नीचे थी, लेकिन इस वर्ष जून तक ही 6,74,021 घटनाएं दर्ज की गई। साइबर सुरक्षित राष्ट्र के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत सरकार को एक मजबूत रणनीति बन बनानी होगी जो सरकारी प्रणालियों, नागरिकों और व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र की सुरक्षा करे। यह न केवल नागरिकों को साइबर खतरों से बचाने में मदद करेगा, बल्कि अर्थव्यवस्था में निवेशकों का विश्वास भी बढ़ाएगा। हाल ही में देश के महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) दिल्ली में साइबर हमला हुआ। यह एजेंसियों द्वारा सुलझाई भी नहीं था कि फिर साइबर हमलावरों ने सरकारी जलशक्ति मंत्रालय के ट्रिवटर अकाउंट को आशिक रूप से हैक कर लिया। देश के

सरकारी वेबसाइटों पर यह दूसरा साइबर हमला था। साइबर अपराधों में बेतहाशा वृद्धि को देखते हुए उपभोक्ताओं को डिजिटल दुनिया में अधिक जागरूक रहना होगा। डिजिटल उपभोक्ताओं को यह समझने की ज़रूरत है कि हम एक बड़ी साइबर श्रृंखला से जुड़े हुए हैं। उनको अपने चंद्र, कंप्यूटर और लैपटॉप को सुरक्षित बनाए रखने के लिए उचित फायरवाल, एंटीवायरस और सुरक्षा मानकों को अपनाना चाहिए। कोई जानकारी आनलाइन साझा करने के दौरान लापवाही नहीं करनी चाहिए। किसी तीसरे पक्ष द्वारा दिए लेंक पर किलक नहीं करना चाहिए। देश को अधिक साइबर सुरक्षित बनाने के लिए हमें अपने स्तर पर सहयोग देने की आवश्यकता है। आंकड़े बताते हैं कि कैसे करते कि जिस दिन से 2022 का फुटबाल विश्वकप की मेजबानी करने का घोषणा हुई, उसी समय से वहां प्रवासी मजदूरों के साथ घोर अत्यधिक अत्यधिक जागरूक रहना होगा।

भी शुरू हो गया। मजदूरों को प्रताडित जाना, उन्हें अमानवीय परिस्थितियों में जाना, उनका वेतन भुगतान समय पर किया जाना, पासपोर्ट जब्त कर लेने से बारह से लेकर अठारह घंटों तक काम ना। पुष्ट खबरों के अनुसार भारत, नादेश, नेपाल और श्रीलंका के आंकड़ों से चला है कि 2011-2020 की अवधि में 27 प्रवासी श्रमिकों की मौत हो हुई। ग से कतर में पाकिस्तान के दूतावास के डंडों ने 2010 और 2020 के बीच 824 प्रस्तानी श्रमिकों की मौतों की पुष्टि की है। एक की हुक्मत इन मृतकों के परिवारजनों हानुमूर्ति जताने के स्थान पर आज भी ग उपहास उड़ा रही है। इससे दुनिया भर जानवाधिकार संगठों एवं कार्यकर्ताओं में फैल गया है। क्या अब भी पापा को यही रहा है कि कतर को मेजबानी देना एक फैसला था?

करते हुए नदियों को जोड़ने पर चिंता जताई है कि इससे समुद्री जीवन को खतरा पैदा हो जाएगा और यह जल विज्ञान और पारिस्थितिकी के अनुकूल नहीं है।

इन भावों परणामा का चिता छाड़ द, ता भा जमाना स्तर पर भूमि अधिग्रहण और पानी के बंटवारे को लेकर राज्यों के बीच दशकों से कायम असहमतियों

के बीच नदियों को जोड़ना एक दुष्कर कार्य है। आज भले गोदावरी-कृष्णा को जोड़ दिया गया हो और केन-बेतवा के जोड़ पर यूपी-एमपी में सहमति बन चुकी हो, लेकिन सतलज-यमुना लिंक नहर को लकर पंजाब, राजस्थान, दिल्ली और हरियाणा के बीच जैसा विवाद है और कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच जो कावेरी जल विवाद है, उनके चलते उनतीस राज्यों में तीस नदियों को जोड़ना आसान नहीं लगता। कोई भी राज्य अपने यहाँ मौजूद नदियों का पानी पड़ोसी राज्यों को देने के लिए तैयार नहीं है, इसी तरह बांध की ऊँचाई बढ़ाने (संदर्भ मुल्लापेरियार बांध) के मुद्दे पर राज्य सरकारों के बीच सिर-फुटव्हल की स्थिति बन जाती है। ऐसे हालात में नदीजोड़ परियोजना कितने राज्यों के बीच किस-किस तरह के विवादों का विषय बनेगी और इसका नतीजा देश के लिए कैसा होगा, इसका पूरा अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। सच्चाई यह है कि नदीजोड़ जैसी कुछ योजनाएं कागजों पर तो अच्छी लगती हैं, लेकिन व्यावहारिकता में इनके रास्ते में कई मुश्किलें हैं। मुद्दा सिर्फ पर्यावरण के लिहाज से संवेदनशील नहीं है, बल्कि कई राजनीतिक मुश्किलें भी हैं, जिससे बड़े परिप्रेक्ष्य में इस परियोजना के साकार होने में कई समस्याएं और सवाल नजर आते हैं। सवाल है कि अगर नदीजोड़ में इतनी मुश्किलें हैं, तो आखिर खेती को सूखे से बचाने और देश को बाढ़ की आपदा से कुछ हद तक सुरक्षित करने का उपाय क्या है?

जंग के महाने से लौटे भार

संघर्ष विराम से जगेगी शांति की उम्मीद



भारत और पाकिस्तान के बीच पिछले कुछ दिनों से जिस तरह युद्ध के हालात बने हुए थे, उसमें यह आशंका गहरी हो रही थी कि कहीं यह ज्यादा जटिल शक्ति न अखिलयार कर ले। खासतौर पर पाकिस्तान की ओर से जिस तरह की प्रतिक्रिया देखी जा रही थी, उसमें ऐसा लग रहा था कि उसे भारत की ओर से आतंकी ठिकानों को निशाना बनाए जाने से परेशानी है और इसी वजह से वह एक दिशाहीन टकराव की ओर बढ़ रहा है। मगर शनिवार को जिस तरह भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम के लिए सहमति बनने की खबर आई, उससे शांति के लिए एक सकारात्मक उम्मीद बढ़ी है। दरअसल, भारत की मंशा पहले भी सिर्फ इतनी ही रही कि उसने बेलगाम आतंकियों को सबक सिखाने के लिए एक 'नपी-नुली और नियंत्रित' प्रतिक्रिया का रास्ता अपनाया था, वह भी उन्हें काबू में करने के लगभग सारे विकल्प खत्म हो जाने के बाद। दूसरी ओर, पाकिस्तान ने आतंकी ठिकानों को निशाना बनाए जाने को अपने ऊपर हमला माना और जवाब में जिस तरह की कार्रवाई शुरू कर दी, उसमें नाहक हडबड़ी और अपरिपक्ता दिख रही थी। मगर इससे स्थिति बिगड़ जाने की आशंका खड़ी हो गई थी। हालांकि इस बीच भारत ने कूटनीतिक स्तर पर अंतरराष्ट्रीय राजनीति में प्रभाव रखने वाले देशों के सामने समूची स्थिति स्पष्ट तौर पर रखी और इस संघर्ष में पाकिस्तान की भूमिका को भी रेखांकित किया। यह आतंकियों के खिलाफ प्रत्यक्ष कार्रवाई से लेकर कूटनीति के मोर्चे पर बहुस्तरीय धोरा था, जिसका दबाव पाकिस्तान साफ महसूस कर रहा था। शायद यहीं वजह है कि अमेरिकी मध्यस्थता के बाद पाकिस्तान के सैन्य संचालन महानिदेशक यानी डीजीएमओ की ओर से भारत के डीजीएमओ को फोन आया और दोनों पक्षों के बीच सहमति बनी कि शनिवार को शाम पांच बजे से जमीन, हवा और समुद्र में सभी तरह की गोलीबारी और सैन्य कार्रवाई बंद कर देंगे। जाहिर है, गंभीर शक्ति लेने की ओर बढ़ते टकराव के बीच पूर्ण और तत्काल संघर्ष विराम की घोषणा शांति की राह तलाशने के लिहाज से एक जरूरी पहलकदमी है और इस पर पाकिस्तान को पहले ही गौर करना चाहिए था। मगर कई बार किसी मसले को इस रूप में भी देखा जाता है कि अगर अंत में सब ठीक कर लिया गया तो वही रास्ता सही है। इसमें कोई दाराय नहीं कि युद्ध किसी भी समस्या का स्थायी हल नहीं है। विंडबना यह है कि कई बार किसी एक पक्ष की द्वेषपूर्ण जिद की वजह से दूसरे को मजबूरन और आखिरी विकल्प के रूप में अपने बचाव में ठोस कदम उठाने पड़ते हैं। पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत के सामने यहीं विकल्प बचा था कि वह आतंकियों की लगातार ऐसी हरकतों को रोकने के लिए एक बड़ी कार्रवाई करे और उन्हें संरक्षण और शह देने वाले ठिकानों को निशाना बनाए। दूसरी ओर, पाकिस्तान ने जो रवैया अपनाया हुआ था, उससे कई बार ऐसा लग भी रहा था कि वह नाहक ही हालात को उलझाने में लगा हुआ है। अदाजा इससे लगाया जा सकता है कि भारत की संघर्षित प्रतिक्रिया के बदले में पाकिस्तान ने भारतीय इलाकों में न केवल बेलगाम गोलीबारी शुरू कर दी, बल्कि इस बात का भी खायाल नहीं रखा कि इसका शिकार आम नागरिक हो रहे हैं। एक ओर भारत की कार्रवाई आतंकियों के खिलाफ थी, तो वहाँ पाकिस्तान की गोलीबारी में पहले दिन दो बच्चों सहित कई लोगों की जान चली गई।

आर्थिक सुस्ती में निवेश की चुनौती

भारत ने वर्ष 2003-04 से कारोबार सुगतना के लिहाज से 48 सुधारों को लागू किया। विश्व बैंक के अनुसार भारत की इस साल की उपलब्धि कई सालों के सुधार के प्रयासों पर टिकी हुई है। भारत लगातार तीसरे साल अर्थव्यवस्था के मामले में शीर्ष-10 सुधारक देशों में शामिल रहा है। भारत के सुधार की प्रमुख वजह दिवालिया कानून को लागू करना, निर्माण परमिट से निपटना, संपत्ति का पंजीकरण करना और सीमा पार व्यापार को बेहतर करना है। कारोबार सुगमता सूची में न्यूजीलैंड शीर्ष पर बना हुआ है।

विं श्व बैंक की राय में भारत में कारोबार करना ज्यादा आसान हो गया है। विश्व बैंक की कारोबार सुगमता सूची या 'ईज ऑफ इडंग बिजनेस' की रैंकिंग में भारत ने इस साल 14 पायदान की छलांग लगाकर अब 63वाँ स्थान हासिल किया है। न्यूजीलैंड पहला स्थान बरकरार रखने में सफल रहा है। सिंगापुर दूसरे और हांगकांग तीसरे स्थान पर रहे। कोरिया पांचवें और अमेरिका छठे स्थान पर रहा। भारत की रैंकिंग वर्ष 2014 में 190 देशों में 142वें स्थान पर थी। इस रैंकिंग में सुधार होने से भारत को ज्यादा विदेशी निवेश आकर्षित करने में मदद मिलेगी। वर्ष 2018 में भारत इस सूची में



लगातार तीसरे साल अर्थव्यवस्था के मामले में शीर्ष-10 सुधारक देशों में शामिल रहा है। भारत के सुधार की प्रमुख वजह दिवालिया कानून को लागू करना, निर्माण परमिट से निपटना, संपत्ति का पंजीकरण करना और सीमा पर व्यापार को बेहतर करना है। कारोबार सुगमता सूची में न्यूजीलैंड शीर्ष पर बना हुआ है। इसके बाद सिंगापुर, हांगकांग का स्थान है। दक्षिण कोरिया सूची में पांचवें और अमेरिका छठे स्थान पर है। यह सूची ऐसे समय में आई है जब भारतीय रिजर्व बैंक, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने देश की आर्थिक वृद्धि दर के अनुमान में कमी की है। भारत में कंपनियों के बीच करारनामा लागू करने और संपत्ति के पंजीयन में लगाने वाले समय को लेकर सुधार न होने से भारत शीर्ष 50 में शामिल होने से चूक गया। करारनामा लागू करने को लेकर भारत की रैंकिंग 190 देशों में 163 वें स्थान पर रही। पिछले साल भी यह इसी स्थान पर रही थी। जाहिर है, एक साल में इसमें कोई भी सुधार नहीं हुआ है। दरअसल, इसमें दो कंपनियों के बीच विवाद के निपटारे की पद्धति, समय और उसकी लागत को ध्यान में रखकर इसकी रैंकिंग तय की जाती है। संपत्ति के पंजीयन में भारत को इस साल इस श्रेणी में 154 वें स्थान मिला, जबकि पिछले साल 166 वां स्थान था। दरअसल, इसकी पारदर्शी प्रक्रिया, पद्धति, लागत आदि कारकों पर रैंकिंग तय होती है। विश्व बैंक के निदेशक (विकास अर्थव्यवस्था) साइमन जेनकोव ने कहा कि लगातार तीसरे साल सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले शीर्ष दस देशों में भारत जगह बनाने में सफल रहा है। इस रैंकिंग के 20 साल के दौर में ऐसी सफलता बहुत कम देशों को मिली है। बिना किसी अपवाद के ऐसा प्रदर्शन करने वाले देश बहुत छोटे और कम आबादी वाले रहे हैं।

